

उत्तर प्रदेश बजट: नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपय आवंटित चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतमबुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपय आवंटित किये हैं।

मुख्य बट्टि:

- यह घोषणा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए की।
- **नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे** के पहले चरण का विकास कार्य चल रहा है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक वाणिज्यिक संचालन के लिये खोलने की योजना है।
- राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये केंद्र की **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN)** और राज्य सरकार की **नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति** के तहत पहल की जा रही है।
- हवाई कनेक्टिविटी के लिये अलीगढ़, आजमगढ़, मोरादाबाद, श्रावस्ती और चित्तूरकूट जैसे चुनदा हवाई अड्डों का विकास किया गया है। मयोरपुर (सोनभद्र) एवं सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डों का विकास कार्य प्रगति पर है।
 - **अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे** के विस्तार के लिये 150 करोड़ रुपय का प्रस्ताव किया गया है।
 - **हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढीकरण** के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिये **1,100 करोड़ रुपय** का प्रस्ताव किया गया है।

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान- UDAN)

- इसे वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)** के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसे **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP)-2016** की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया और यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू की गई थी।
- योजना के तहत **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान (Regional Connectivity Fund- RCF) की व्यवस्था की गई थी।
 - VGF का अर्थ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त या स्थगित अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से कम है।